

प्रेषक,

नीतीश्वर कुमार,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बांदा, चन्दौली, चित्रकूल, देवरिया, एटा,
फैजाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, इटावा, जालौन, कानपुर नगर, कांसगंज, ललितपुर, महोबा,
पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती व सुल्तानपुर।

शिक्षा अनुभाग -6

लखनऊ: दिनांक: ०८ नवम्बर, 2013

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड/एन०जी०ओ० के स्तर पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा० /727/2013-14 दिनांक 08 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-149/79-6-04-1(6)/2000 टी०सी०-3 दिनांक 25-6-04, संख्या-1646/79-6-04-1(6)/2000 टी०सी०-3 दिनांक 23-07-04 तथा शासनादेश संख्या-978/79-6-2011-1(6)2000टीसीvii दिनांक 6 जुलाई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25-6-04 तथा दिनांक 23-07-04 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु आदेश निर्गत किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 से योजना का विस्तारीकरण प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया गया है।

3- जनपद स्तर पर योजना संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया गया है :-

1-मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
3-जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4-जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
5-जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
6-मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7-समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8-जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9-परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०	सदस्य
10-जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11-जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
12-संबंधित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
13-भारतीय खाद्य निगम/उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी	सदस्य

4- अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं० 977/79-6-2012 दिनांक 22.08.2012 द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, जालौन, बांदा, श्रावस्ती, गोण्डा, बदायूं एवं आजमगढ़ में अवशेष खाद्यान्न के सामायोजन/वसूली हेतु आदेश जारी किये गये थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है, उक्त आदेशों के उपरान्त भी मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की वसूली पूर्णरूप से अद्यतन नहीं की जा रही है।

GORP

5- योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) तथा परिवर्तन लागत (मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु दी जाने वाली धनराशि) विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा-जोखा रखे जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-13242-312/2007-08 दिनांक 06-11-07 द्वारा मध्यान्ह भोजन पंजिका रखे जाने की व्यवस्था की गयी। उक्त पंजिका में विद्यालय स्तर पर योजना से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या तथा वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन का विवरण अंकित किया जाता है। मध्यान्ह भोजन पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग प्राप्त होता है इसके आधार पर जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात होती है।

6- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न की वसूली हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करायें :-

(1)- पूर्व कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न की वसूली वर्तमान बाजार मूल्य पर किये जाने का निर्णय लिया गया। खाद्यान्न के वर्तमान बाजार मूल्य को खाद्यान्न विपणन संस्थाओं/भारतीय खाद्य निगम से ज्ञात किया जा सकता है। भविष्य में इस प्रकार की वसूली की कार्यवाही की स्थिति में तत्समय लागू बाजार मूल्य पर वसूली की जायेगी।

(2)-समस्त अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली धनराशि के रूप में कर कोषागार के प्राप्ति हेतु संख्या-"0202-01-800-01 अन्य प्राप्तियां" में जमा करायी जाय। पूर्व में यदि किसी जनपद में वसूली की धनराशि किसी अन्य खाते में रखी गयी हो, तो उसे भी कोषागार में जमा करा दिया जाय। अवशेष खाद्यान्न की शत-प्रतिशत वसूली संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधानों से की जाय, परन्तु अवशेष परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी मात्रा में की जाय। संबंधित ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सचिवों, जिनसे अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली अपेक्षित है, की सूची वसूली की धनराशि के विवरण सहित जनपदों से प्राप्त कर प्राधिकरण स्तर पर सुरक्षित रखी जाय। गबन के कृत्य हेतु दोषी ग्राम प्रधानों/ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाय। गबन हेतु उत्तरदायी ग्राम प्रधानों की सूचना राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जाय ताकि आगामी चुनावों में उनके एवं उनके परिवारजनों द्वारा उम्मीदवारी प्रस्तुत करने की दशा में उनकी अर्हता/अनर्हता के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त गबन हेतु उत्तरदायी ग्राम प्रधानों की सूची जनपद स्तर पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जाय।

(3)-पूर्व कार्यदायी संस्थाओं के स्तर पर अधिक मात्रा में अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली प्रक्रियाधीन होने के कारण जिन जनपदों में खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की कमी की सूचना प्राप्त होती है, उन जनपदों में भ्रमण कर अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की कमी के कारण बच्चों को भोजन का वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा वास्तविक रूप में योजना के उक्त कारणों से दुष्प्रभावित होने की स्थिति में जनपद से प्रमाणक प्राप्त कर कठिनाई निवारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जाय।

7- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का विदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के पूर्व कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत हेतु प्रस्तर-5 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन किए जाने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नोटिस देगा तथा नोटिस में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस संबंध में यदि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पक्ष में कोई तथ्य प्रस्तुत करना है तो एक सप्ताह में अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप से साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित कार्यदायी संस्था से भू-राजस्व के बकायों की भांति किये जाने हेतु स्पष्ट मार्ग-पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावानुसार

निम्नलिखित स्तरों पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही बाधित होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाए की भांति सम्पादित की जायेगी, ताकि अभीष्ट समायोजन किया जा सके और योजना का क्रियान्वयन सुगम हो सके ।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
NIC
(नीतीश्वर कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
- 4- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा), उ०प्र० ।
- 5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० ।

आज्ञा से,
3/11/13
(अमर नाथ वर्मा)
विशेष सचिव।

क्र०सं०	जनपद	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है।	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य	ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है।	जारी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी०) की संख्या	एक 0 आरोआरो की संख्या	जारी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी०) में खाद्यान्न की कुल मात्रा	जारी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी०) में कुल मात्रा का मूल्य	कॉलम-3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा	9/0	8=7*1 00/3	जारी किये गये वसूली आदेशों के विरुद्ध मा० न्यायालय से योजित वार्दों की संख्या	मा० न्यायालय से योजित वार्दों के सापेक्ष अद्यतन कूल कार्यवाही की स्थिति	अन्य टिप्पणी
1			3A	4	5	5A	6	6A	7		8A	8B	9	
22	SAHARANPUR	136.88							10.36	7.57	0			जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदनानुसार अधोस्वाक्षरी कार्यालय के पत्र सं० मिड डे मील 15728-16504 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा पूर्व प्रधानों को रिकवरी हेतु नोटिस जारी किये गये है।
23	SHRAWASTI	831.66	128.82	244	244	5	831.66	128.82	30.84	3.71	47			25 वार्दों का निस्तारण किया गया है। शेष 22 वार्दों का निस्तारण करवा जा रहा है।
24	SULTANPUR	2556.78	144.18	689		0	239.76	13.51	0.00	0.00	0			
	TOTAL	27556.13	679.23	9291	2426	5	11339.72	548.56	1610.76	5.85	84			

शासनादेश संख्या: 978 / 79-6-2011-1(6)2000टी0सी0 वी के अनुक्रम में खाद्यान्न वसूली सम्बन्धी सूचना

ऐसे जनपद जहां रिकवरी की जानी है। (कुल-24)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है।	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य	ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है।	जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) की संख्या	एफ0. आई0आर0 की संख्या	जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा	जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य	कॉलम-3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा	%	जारी किये गये वसूली आदेशों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में योजित वादों की संख्या	मा0 न्यायालय में योजित वादों के सापेक्ष कूल कार्यवाही की संख्या	ग्राम प्रभारी
1	2	3	3A	4	5	5A	6	6A	7	8=7*100/3	8A	8B	9
1	AMBEDKAR NAGAR	4155.89	279.77	990	990	0	4155.89	279.77	22.00	0.53	0		आर0सी0 जारी करवाकर वसूली का कार्यवाही करायी जा रही है।
2	AURAIYA	61.87		0					0.00	0.00	0		मुख्य विकास अधिकारी औरैया के द्वारा अपने पत्र संख्या एम0डी0एम0 / 3025-27 / 2012-18 / दिनांक 27.06.2012 के द्वारा निर्देशक मथानन्द भोजन प्राधिकरण उ0प्र0, मथानन्द से सात बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश चाहे गये हैं। अपेक्षित निर्देश प्राप्त होने के कारण जनपद में रिकवरी की कार्यवाही लम्बित है।
3	AZAMGARH	1682.45		942	49		271.48		10.54	0.63	0		सम्बन्धित प्रधानों के विरुद्ध आर0सी0 जारी करने हेतु प्रस्तुत पत्रावली के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रधानों के साथ ही सचिवों के विरुद्ध भी आर0सी0 जारी की जाये, जिसके अनुक्रम में सम्बन्धित सचिवों को विवरण जिला पंचायत राज अधिाधी आजमगढ़ से लिखित रूप से मांगा गया है जो अद्यतन अपेक्षित है।
4	BALLIA	391.63		109	3		11.13		0.00	0.00	0		
5	BANDA	4384.90		353	72		1091.90		0.00	0.00			
6	BUDAUN	924.60	126.46	130	130	0	924.60	126.46	200.00	21.63	36		आर0सी0 के सापेक्ष जनपद के अधिकतर पूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की गयी हैं जिनमें से करिषय में प्रतिशत पत्र दाखिल किया जा चुका है शेष में कार्यवाही गरिमान है।
7	CHANDAUJI	1020.87		377	377		1020.87		80.36	7.87	0		जिलाधिकारी के पत्रांक/एम0डी0एम0 / 1842-48 / 2012-13 दिनांक 04.08.2012 द्वारा कुल 388 प्रधानों के विरुद्ध आर0सी0 करने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), चन्दौली को सूची प्रेषित की गयी है। जिसके विरुद्ध कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल की गयी, जिसमें कुल 76 ग्राम प्रधानों की जिलाधिकारी महोदय के सुनवाई के उपरान्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।
8	CHITRAKOOT	90.59		224	0		0.00		86.47	95.45			
9	DEORIA	442.00		1931							0		
10	ETAH	153.00	0.00	385	0		0.00	0.00	25.00	16.34	0		
11	ETAWAH	54.50		112	112		54.50		49.50	90.83	0		Due to death of pradhans rest foodgrain cant be recover.
12	FAIZABAD	101.72		148	1		1.34		1.34	1.32	0		पूर्व का अवशेष खाद्यान्न पुराने ग्राम प्रधानों से नवीन ग्राम प्रधानों को प्राप्त करये जाने की कार्यवाही गरिमान है।

क्र०सं०	जनपद	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी-वस्तुली की जानी है।	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य	ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वस्तुली की जानी है।	जारी किये गये वस्तुली आदेशों (आर०सी०) की संख्या	एफ० आर० की संख्या	जारी किये गये वस्तुली आदेशों (आर०सी०) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य	जारी किये गये वस्तुली आदेशों (आर०सी०) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य	कॉलम-3 के सापेक्ष अद्यतन किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा	%	जारी किये गये वस्तुली आदेशों के विरुद्ध मा० न्यायालय में योजित वादों की संख्या	मा० न्यायालय में योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति	अन्य टिप्पणी
1	2	3	3A	4	5	5A	6	6A	7	8=7*100/3	8A	8B	9
22	SAHARANPUR	136.88							10.36	7.57	0		जिलाधिकारी महोदय द्वारा गये अनुमोदनानुसार अथोडस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं० मिड डे मील 15728-16504 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा पूर्व प्रधानों को रिकवरी हेतु नोटिस जारी किये गये है।
23	SHRAWASTI	831.66	128.82	244	244	5	831.66	128.82	30.84	3.71	47	26 वादों का निस्तारण किया गया है। शेष 22 वादों का निस्तारण करण जा रहा है।	
24	SULTANPUR	250.78	144.18	689		0	239.76	13.51	0.00	0.00	0		
TOTAL		2756.13	679.23	9291	2448	5	11339.72	548.56	1610.76	5.85	84		

क्र0सं0	जनपद	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है।	ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य	ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है।	जायी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी0) की संख्या	एक0 आरो की संख्या	जायी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा	जायी किये गये वसूली आदेशों (आरोसी0) में कुल मात्रा का मूल्य	कॉलम-3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा	%	जायी किये गये वसूली आदेशों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में योजित वादों की संख्या	मा0 न्यायालय में योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति	अन्य टिप्पणी
1	2	3	3A	4	5	5A	6	6A	7	8=7*100/3	8A	8B	9
13	GONDA	1275.15		275	275		1171.16		783.69	61.46	0	समस्त वादों का निस्तारण किया गया है।	
14	HAMIRPUR	800.65		223	0		0.00		0.00	0.00			खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से वसूली की कार्यवाही गतिमान है।
15	HATHRAS	10.57	0.00	3	3	0	10.97	0.00	0.00	0.00	1	C.A. File	
16	JALAUJ	2950.09		417	0		0.00		0.00	0.00	0		प्राधिकरण से रिसीट हेड प्राप्त न होने की स्थिति में वसूली आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। जिलाधिकारी द्वारा 359 ग्राम प्रधानों की रिकवरी हेतु सूची अनुमोदित कर दी गयी है। रिकवरी की वसूली आदेशों के सम्बन्ध में खाद्यान्न मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु रिसीट हेड प्राप्ति के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अनुरोध पत्र द्वितीय प्रेषित किया गया है।
17	KAASGANJ	1869.09	0.00	387	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0		शासनादेश के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 25.07.2012 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व प्रधानों एवं प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित करते हुये अभिलेखों का मिलान कर लिया जाये एवं वार्षिक अवशेष खाद्यान्न की मात्रा आकलित करते हुये तत्काल विद्यालय के प्र0अ0 को हस्तगत करा दी जाये। उक्त के अन्तर्गत में अवशेष खाद्यान्न की वसूली की कार्यवाही करायी जाये।
18	KANPUR NAGAR	752.00		461	0				256.72	34.12	0		जिलाधिकारी के टीप आदेश दिनांक 05.03.2012 के क्रम में 139 पूर्व ग्राम प्रधानों के विरुद्ध एक0आर्ड0आरो दर्ज करा दी गयी है। जिसके क्रम में अभी तक 53.94 मी0टन खाद्यान्न जिसका मूल्य रु0 67.029 लाख है, की वसूली की जा चुकी है।
19	LALITPUR	277.00		297	0		225.68		53.94	19.46	0		जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खाद्यान्न के मूल्य की वसूली की जा रही है अब तक कुल धनराशि रु0 22 लाख की वसूली की जा चुकी है।
20	MAHOBA	1328.78		151	151		1328.78		0.00	0.00			443 ग्राम पचायतों के ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किये गये हैं। तत्क्रम में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ग्राम प्रधानों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों का परीक्षणोपरान्त संबंधित ग्राम प्रधानों को अन्तिम नोटिस जारी करते हुए आरोसी0 जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
21	PILIBHIT	1296.00	0.00	443	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0		